

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4388
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
29 श्रावण, 1947 (शक)

उद्योगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

4388. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) विनिर्माण उद्योग के कितने प्रतिशत हिस्से ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सफलतापूर्वक शामिल किया है;
- (ग) अगले दशक के लिए एआई विनिर्माण बाजार में भारत की अनुमानित वृद्धि का व्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने विनिर्माण उद्योगों में एआई के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार प्रौद्योगिकी को सभी के लिए सुलभ बना रही है। वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास और उपयोग को लोकतात्त्विक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, अंततः विभिन्न क्षेत्रों में जीवन में सुधार हुआ है।

वर्तमान में भारत में एआई इकोसिस्टम:

- एआई सहित तेजी से बढ़ते भारत के तकनीकी क्षेत्र इस वर्ष वार्षिक राजस्व में 280 बिलियन डॉलर को पार करने का अनुमान है
- इस क्षेत्र में 6 मिलियन से ज्यादा लोग कार्यरत हैं
- एआई पर केंद्रित 500+ सहित 1,800+ वैश्विक क्षमता केंद्र हैं।
- भारत में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप; पिछले वर्ष भारत में 89% नए स्टार्टअप एआई-संचालित थे
- नैसकॉम एआई एडॉप्शन इंडेक्स पर भारत का स्कोर 4 में से 2.45 है, जो दर्शाता है कि 87% उद्यम सक्रिय रूप से एआई को स्वीकार कर रहे हैं।
- एआई अपनाने में अग्रणी क्षेत्र औद्योगिक और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता पैकेज सामान (सीपीजी) और खुदरा, बैंकिंग वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई), और स्वास्थ्य सेवा हैं, जो एआई के संभावित मूल्यवर्धन में लगभग 60% का योगदान करते हैं।
- बीसीजी सर्वेक्षण के अनुसार, 26% भारतीय कंपनियों ने अपने सभी परिचालनों में बड़े पैमाने पर एआई परिपक्ता हासिल की है।
- स्टैनफोर्ड एआई रैंकिंग जैसी वैश्विक रैंकिंग भारत को एआई कौशल, क्षमताओं और एआई का उपयोग करने संबंधी नीतियों के क्षेत्र में शीर्ष देशों में स्थान देती है
- भारत, गिटहब एआई परियोजनाओं में द्वितीय सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो इसके जीवंत डेवलपर समुदाय का प्रमाण है।

इस सुदृढ़ नींव पर निर्माण करते हुए, एआई को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए वर्ष 2024 में इंडियाएआई मिशन शुरू किया गया था। यह भारत के विकास लक्ष्यों के साथ सरेखित एक सुदृढ़ और समावेशी एआई इकोसिस्टम स्थापित करता है। इंडियाएआई मिशन के सात स्तंभ निम्नानुसार हैं:

- इंडिया एआई कंप्यूट क्षमता:** इसका उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्टअप सहित सभी को किफायती कीमत पर उच्च-स्तरीय कम्प्यूट शक्ति (जीपीयू) प्रदान करना है।
- इंडियाएआई फाउंडेशन मॉडल:** भारतीय डेटासेट और भाषाओं पर प्रशिक्षित भारत के अपने बड़े मल्टीमॉडल मॉडल (एलएमएम) विकसित करना। इसका उद्देश्य जनरेटिव एआई में संप्रभु क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
- एआईकोश:** एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिये बड़े डेटासेट विकसित करना। एआईकोश एक एकीकृत डेटा प्लेटफ़रॉम है जो सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से डेटासेट को एकीकृत करता है।
- इंडियाएआई अनुप्रयोग विकास पहल:** इस स्तंभ का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शासन और सीखने की अक्षमता के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में भारत विशिष्ट चुनौतियों के लिए एआई अनुप्रयोगों को विकसित करना है।
- इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स:** एआई क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की संख्या में वृद्धि करके भारत में एआई कुशल पेशेवरों को विकसित करना। यह भारत भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब्स स्थापित करने की भी कल्पना करता है।
- इंडियाएआई स्टार्टअप वित्तपोषण:** एआई स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- सुरक्षित और विश्वसनीय एआई:** जिम्मेदार एआई को अपनाने को सुनिश्चित करने के लिये सुदृढ़ शासन ढांचे के साथ नवाचार को संतुलित करना।

सरकार, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों के माध्यम से, लागू कानूनों, विनियमों और सर्वोत्तम पद्धतियों के सरेखण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने को बढ़ावा दे रही है।
